Fourteenth Loksabha

Session : 7
Date : 22-02-2006

Participants : Agarwal Shri Dhirendra

an>

Title : Need to give due weightage to the suggestions of MPs in implementation of Centrally-sponsored schemes in their Constituencies.

डॉ. धीरेन्द्र अग्रवाल (चतरा) : उपाध्यक्ष महोदय, देश के विकास एवं लोगों को सुविधाएं दिलाने हेतु केन्द्र सरकार की कई प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, उनका फायदा लोगों को हो एवं आबंटित राशि का पूरा उपयोग हो रहा है या नहीं इसके लिए केन्द्र सरकार ने कोई निर्देश नहीं दिए हैं, जिसके कारण इन योजनाएं के लिए आबंटित होने वाले पैसे का केवल 15 से 20 प्रतिशत ही इन कामों पर खर्च हो रहा है। इन कार्यों को पूरा करने में स्थानीय सांसदों के सुझावों को नहीं माना जाता है। राज्यों में जो राज्यों की तरफ से योजनाएं चलाई जाती हैं, उनमें स्थानीय विधायकों की राय एवं सुझाव माने जाने हेतु राज्य सरकारों के निर्देश हैं, परन्तु केन्द्र सरकार की प्रायोजित योजनाओं में स्थानीय सांसदों की बात नहीं मानी जाती है, जिसका प्रभाव यह होता है कि राज्य के अनपढ़ एवं कम पढ़े-लिखे लोग समझते हैं कि उनके लिए केन्द्र सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। केवल राज्य सरकार ही उनके लिए काम कर रही है। केन्द्र सरकार कई गैर संगठनों को कई योजनाओं को लागू करने हेतु केन्द्र स्तर पर पैसा देती है। उनमें भी सांसदों की कोई भूमिका नहीं है और न ही उनकी कोई राय मानी जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की जो योजनाएं सांसदों के क्षेत्र में चल रही हैं और निगरानी एवं सतर्कता कमेटी के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की हैसियत से राज्य सरकार के अधिकारों की शिकायतें केन्द्र सरकार को करते हैं, वह भी राज्य सरकार के अधिकारियों को जांच हेतु भेजी जाती है, जो कि न्यायसंगत नहीं है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि केन्द्र सरकार के जितने प्रायोजित कार्यक्रम हैं, उनके क्रियान्वयन में स्थानीय सांसदों की राय एवं सुझाव अवश्य माने जाएं एवं ऐसे कार्यों के उद्घाटन एवं शिलान्यास स्थानीय सांसदों से कराये जाने हेतु निर्देश दिये जाएं और ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यक्रम की निगरानी एवं सतर्कता के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की हैसियत से शिकायत की जांच केन्द्र स्तर पर करके राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये जाएं।